UGC APPROVED JOURNAL - 47940
© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 05 , Issue : 02 | January – March 2018

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सुधार पर एक विवेचना

डॉ० ओम प्रकाश साहु
व्याख्याता
श्रम एवं समाज कल्याण विभाग,
सीता राम साहु कॉलेज, नवादा. बिहार |

सार

भारत में बैंकिंग क्षेत्र में एक सेवा प्रधान क्षेत्र है जिसका उद्देश्य वस्तुओं का निर्माण व विक्रय न होकर सेवाएं प्रदान करना है । बैंकिंग सेवाओं की उपयुक्तता, प्रभावकारिता एवं लाभदायकता हेतु यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि बैंक कर्मचारियों को बैंकिंग विधियों, नीतियों, प्रक्रियाओं व व्यवहारों का पर्याप्त ज्ञान हो । एक नये विकासोन्मुखी वातावरण की रचना हेतु हमारे बैंक वर्तमान में अपनी गतिविधियों एवं प्रतिक्रियाओं में समय की पुकार के अनुकूल क्रांतिकारी परिवर्तन करने में सतत् प्रयत्नशील है । इस हेतु बैंक कर्मचारियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा चुकी है ।

मुख्य शब्द : बैंकिंग , सेवाएं, नीतियों, वातावरण इत्यादि ।

प्रस्तावना

वर्तमान में हमारे बैंक विकस की नित नई अवस्थाओं की ओर अग्रसर हो रहे है । बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों द्वारा शाखाओं के विस्तार, व्यापार वृद्धि और तीव्र मार्केटिंग को देखते हुए बड़े स्तर पर रोजगार की संभावनाएं उभर रही है । देश में कई बैंक केम्पस सिलेक्शन के माध्यम से युवाओं की भर्ती करके उन्हें पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करवा रहे हैं । यह स्थिति बैंक कर्मियों के सेवानिवृत्त होने के कारण खाली हो रहे पदों को भरने के लिये सहायक हो रही है । फीस आधारित आय में वृद्धि की माँग को देखते हुए बैंक बीमा पॉलिसी, म्युचअल फण्ड योजना और अन्य योजनाओं के वितरण जैसी गतिविधियों पर बल दे रहे है । कोर बैंकिंग सोल्युशन और नये युग की बैंकिंग को देखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक नये क्षत्री जैसे टेली-कालिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और टेक-सपोर्ट के क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि कर रहे हैं । यह कहना अब अधिक तर्कसंगत है कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र एक आकर्षक एवं नये कलेवर के रूप में हम सभी को आकर्षित कर रहा है ।

[1] बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। देश में बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत को इतिहासकार लगभग 18वीं शताब्दी से ही मानते हैं| इसके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने आधुनिक बैंकिंग प्रणाली को लाकर भारत की अर्थव्यवस्था में क्रांति कर दी थी। अंग्रेजों ने सुनियोजित

UGC APPROVED JOURNAL - 47940
© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 05 , Issue : 02 | January – March 2018

तरीके से धन की उगाही के लिये तीनों प्रेसीडेंसियों मसलन मद्रास, बंबई और बंगाल में बैंकों की स्थापना की। इसके बाद तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई।

[2] भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1955 को इम्पीरियल बैंक की सभी संपत्तियों का अधिग्रहण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है| इसे राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में उन बैंकों को रखा जाता है जो 1969 के राष्ट्रीयकरण और उसके बाद सरकार के अधीन आये हैं।

[3] यह तो बात थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में| अब बात करते है केन्द्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 1926 हिल्टन यंग कमीशन ने इस बात का सुझाव दिया था कि इम्पीरियल बैंक से अलग एक केन्द्रीय बैंक को स्थापित किया जाना चाहिये जो विदेशी विनिमय कोष प्रबंधन के साथ-साथ नोट भी जारी कर सके। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि हिल्टन यंग कमीशन पहला कमीशन था जिसने रिजर्व बैंक को लाने की बात कही थी|

[4] 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के जरिये 1 अप्रैल,1935 से रिजर्व बैंक ने कार्य करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि वर्मा विभाजन के बाद रिजर्व बैंक ने 1942 तक वहाँ की करेंसी अथॉरिटी और 1947 तक वहाँ की सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य किया था। देश के विभाजन के बाद 1948 तक इसने पाकिस्तान के सेन्ट्रल बैंक के रूप में भी कार्य किया था। वर्ष 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और तब से यह देश का केन्द्रीय बैंक है।

[5] इस समय देश में RBI और SBI के अलावा भी कई अन्य व्यापारिक बैंक कार्य कर रहे थे। फिर भी ऐसा लगातार महसूस किया जा रहा था कि इन बैंकों के द्वारा कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, गाँव और कस्बों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उस समय सरकार ने देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिये 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया । इस कदम को और विस्तार देते हुए सरकार ने 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन सबके बावजूद भी इसके वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसलिए सरकार ने बैंक क्षेत्र में सुधार के लिये कई आयोगों का गठन किया।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

1 **नई शाखाओं की स्थापना को प्रोत्साहन:** देश में बैंकिंग सुविधाएं कम है अतः उन में वृद्धि करने के लिए उदारता पूर्वक शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन स्थानों पर बैंकों की शाखाएं नहीं है उन स्थानों पर शाखाएं खोल सके विशेष रूप से

UGC APPROVED JOURNAL - 47940
© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 05 , Issue : 02 | January – March 2018

ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की शाखा का एक जाल चलाया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण जनता भी बैंकिंग सेवा से लाभ उठा सकें।

2.**आधुनिक बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धि :**भारतीय बैंकों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं देनी चाहिए इसके लिए व्यक्तिगत ऋण प्रोत्साहित करना चाहिए।

3 **प्रशिक्षण व्यवस्था:** कर्मचारियों को प्रशिक्षण करने के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए तथा कोई भी कर्मचारी बैंक की खिड़की पर नहीं दिखाना चाहिए जब तक कि उसने प्रशिक्षण प्राप्त न कर लिया हो इससे बैंक सेवा में जन सुधार होगा वह जनसाधारण के साथ अच्छा व्यवहार होगा।

4 **यंत्रों का उपयोग:** खातों को सही रखने एवं ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए भी आवश्यक है कि बैंकों में यंत्रों का उचित उपयोग किया जाए।

5.**बैंकों का एकीकरण** : जो बैंक दुर्बल है या छोटे हैं उन्हें दबाव डालकर बड़े बैंकों में मिला देना चाहिए इससे देश की बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

उपसंहार

बैंकों का स्वरूप लगातार बदल रहा है। पहले जहाँ बैंकों में लंबी-लंबी कतारें लगी रहती थीं, वहीं अब तकनीक ने इस कार्य को सरल और सुगम बना दिया है। तकनीक का प्रयोग करके पेमेंट बैंकों ने इस कार्य को और आसान बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक बैंकिंग विशेषकर कैशलेस अर्थव्यवस्था बैंकिंग लेन-देन के डिजिटलीकरण के दौर में चिंता का विषय जरूर है। परन्तु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आईआईटी जैसे संस्थानों के साथ मिलकर विभिन्न तरीकों से इससे निपटने के प्रयास किये हैं। जन-धन योजना और डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं के माध्यम से बैंकिंग के जरिये वित्तीय समावेशन पर सरकार बहुत जोर दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुँच न हो पाना भी चिंता का विषय है। क्योंकि दुर्गम और कठिन क्षेत्र होने के कारण कई क्षेत्रों में अभी भी बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने बड़ी संख्या में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की नियुक्ति कर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकों तथा ग्रामीण जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। इसी प्रकार बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिये हाल ही में सरकार ने तीन बैंकों के विलय का फैसला लिया है। इसमें देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं।

कुल मिलाकर ,भारत का आज का बैंकिंग स्वरूप बदलते परिवेश में नए कलेवर अपना रहा है| ऐसे में जरूरत इस बात की है कि यह कलेवर भारतीय जनता के सामाजिक-आर्थिक विकास को और बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

[1] माथुर, के०बी०एल० (2010), स्वस्थ और समर्थ बैंकिंग क्षेत्र योजना, फरवरी 2010

[2] जायसवाल, गोपाल (2010), वित्तीय सुधारों में बैंकिंग, योजना, फरवरी 2010, पृ0 31

[3] मिश्र एवं पुरी (2008), "भारतीय अर्थव्यवस्था" हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई.

[4] कुलश्रेष्ठ, ०(2005), "वित्तीय प्रबंध", साहित्य भवन पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि. आगरा.

[5] सिन्हा, वी०सी० (2003), "अन्तराष्ट्रीय अर्थशास्त्र" मयूर पेपरबैक्स, नोएडा.

[6] माथुर, बी०एल० (2002), "आर्थिक नीति एंव प्रशासन" आरबीएसए पब्लिशर्स जयपुर.